आर.एन.आई. नं0 51794/91

पोस्टल रजि. नं. जी.पी.ओ. एल.डब्लू/एन.पी. 59/2013–2015

उपभोक्ता फ्रंट

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

वर्ष–27 अंक–9–10 (संयुक्तांक) (फरवरी प्रथम–द्वितीय) लखनऊ, बुधवार 01 से 28 फरवरी, 2017 पृष्ठ–8 मूल्य 1.00 रुपये

वित्त मंत्री के पिटारे से सरकारी बैंकों को मिले 10,000 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की मार झेल रहे सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान इंद्रधनुष योजना के तहत पूंजी के तौर 10,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इसके पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीकरण के लिए वित्त वर्ष 2015–16 और 2016–17 में क्रमशः 25,000–25,000 करोड़ रुपये के दो किस्तों का भुगतान कर दिया है। अब सरकार दो वित्त वर्ष के दौरान देश के सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेगी. इस राशि में 10,000 करोड़ रुपये 2017 और 10,000 करोड़ रुपये 2018 में उपलब्ध कराये जायेंगे. इसी क्रम में वित्त मंत्री जेटली ने संसद में बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराने की घोषणा की है।दरअसल, करीब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की एनपीए की मार झेल रहे सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए सरकार ने 2015 इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत बैंकों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने की बात शामिल की गयी थी. इंद्रधनुष में सात रंग की जगह ए से लेकर जी तक सात अल्फाबेट शामिल किये गये हैं। इसके तहत एक तय फॉर्मूले के मुताबिक बैंकों को चार साल में 70,000 करोड़ रुपये देने की योजना बनायी गयी है।

सरकार ने बीते दो वित्त वर्ष के दौरान देश के करीब 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दो किस्तों में 25,000–25,000 करोड़ रुपये के हिसाब से करीब 50,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये हैं. इसी 70,000 करोड़ रुपये में से बाकी के 20,000 करोड़ रुपये में 10,000 करोड़ रुपये की राशि इन 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान उपलब्ध कराया जायेगा।

बजट हर तबके का रखा गया ध्यान : मोदी

नई दिल्ली। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री को बधाई। उन्होंने कहा कि बजट में दाल से लेकर डेटा पर ध्यान, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक पर ध्यान दिया गया। ये बजट अर्थतंत्र और देश को नई मजबूती देगा, देश विकास की ओर बढ़ेगा।मोदी ने कहा कि ये बजट सबके लिए है, गरीब के लिए भी है। हाइवे–रेलवे से लेकर सरल इकॉनमी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, सभी कुछ की बेहतरी यह बजट समेटे है। बजट से अर्थतंत्र को मिलेगी ताकत।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में मिडिल क्ल्लास को राहत देते हुए इनकम टैक्ल्स घटाया है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों को 2000 रुपए से ज्ध्यादा के नकद चंदे पर भी रोक लगा दी गई। कालेधन पर रोक लगाने वाले फैसले के तहत3 लाख रुपए से ज्ध्यादा के कैश लेनदेन को भी बंद कर दिया गया है। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2.5 से 5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर अब 5 प्रतिशत की दर से टैक्ल्स लगेगा।

बजट में झारखंड और गुजरात में एम्ल्स खोले जाने, मनरेगा का बजट आवंटन बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपए करने, प्रध ाानमंत्री आवास योजना में 23 हजार करोड़, प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है।

केंद्रीय बजट पेश, पूरी नहीं हुई बिहार को विशेष पैकेज या या दर्जा देने की उम्मीद

पटना। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय आम बजट पेश किया। बिहार के लोगों को आम बजट से कुछ विशेष हासिल हुआ हो, ऐसा नहीं लगता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज को लेकर भी बजट मिलने की उम्मीद जताई गई थी, जो पूरी नहीं हो सकी।

बजट किसी भी सरकार की आर्थिक नीतियों का आइना होता है। नोटबंदी के बाद पेश होने वाले इस बजट से बिहार के लोगों को उम्मीद थी। खासकर इसलिए कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी समानांतर उठती रही है। राज्य के वित्तमंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी मानते हैं कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की रेटिंग लगातर कम हो रही है। डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में भी गिरावट आ ही है। इसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई है, जिसका असर रोजगार और राज्यों के कर उगाही पर गंभीर रूप से पड़ा है।

पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और जाने–माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि जब तक राज्यों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। चौधरी का मानना है कि बिहार के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने की जरूरत थी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान भी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इससे बिहार में नए उद्योग स्थापित हो सकेंगे। नए उद्यमियों को बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष छूट मिलने का प्रावधान भी होना चाहिए था।

आम बजट से बाजार को बड़े बदलाव की उम्मीद

देहरादून। आम बजट–2017 से बाजार को बड़े बदलाव की उम्मीद है। लोग लुभावने के बजाय सुधारवादी बजट की आस लगाए हैं। उनका मानना है इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बचत होगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा।

शिवपाल पर नहीं करूंगा कोई कार्रवाई : अखिलेश

लखनऊ। नई पार्टी बनाने और दूसरे दलों से लड़ रहे सपा के बागियों के लिए प्रचार करने के शिवपाल के बयान के बावजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाचा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं हैं। एक कार्यक्रम में सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि वो शिवपाल यादव पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मुझ पर कार्रवाई हुई तो मैं यहां तक पहुंच गया, इसलिए अब शिवपाल पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा।

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में प्रचार के सवाल पर सीएम ने कहा कि पार्टी में इतनी आजादी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि कोई प्रचार करने जाए, लोग किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।

अखिलेश ने घोटालेबाज कांग्रेस से हाथ मिलाया है : भाजपा

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं और अपराधियों के संरक्षक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोटालेबाज कांग्रेस से हाथ मिलाया है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'अच्छे दिनश नहीं देख पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''घोटाले बाज कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर भ्रष्टाचारियों, भूमाफियों और अपराधियों के संरक्षक समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों, किसानों और आम आदमी के लिए लाये गये अच्छे दिन तो नहीं देख पा रहे हैं.श्श मौर्य ने कहा, ''.... लेकिन राजधानी में रोडशो के दौरान अखिलेश और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का रास्ता रोकने वाले बिजली के लटकते तारों ने सपा का विकास के नाम जनता के साथ किये गये

फरेब की हकीकत जरुर बयां कर दी है।

उन्होंने कहा, ''अखिलेश राज में बिजली वितरण ढांचा दुरुस्त करने के नाम पर 100 करोड़ रुपए की बंदरबांट कर ली गयी, लेकिन न तो झूलते तारों की हालत सुधरी और न ही बिजली मिल रही. यह स्थिति राजधानी में है तो प्रदेश के अन्य जिलों में ध्वस्त हो चुकी विद्युत व्यवस्था का अंदाजा स्वतरू ही लगाया जा सकता है।

सम्पादकीय

उम्मीदों से लबरेज रेल बजट

ठाकुर रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का नया इतिहास शुरू हो गया। पिछले 92 साल से अब तक रेल बजट को आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता रहा है। सरकार पहली बार बजट के एक महीना पहले पेश कर रही है। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता रहा है लेकिन सरकार अबकी पहली फरवरी को पेश कर रही है। इसमें सरकार का तर्क है कि बजट के प्रावधानों को लागू करने के लिए वक्त मिलेगा। मौजूदा रेल बजट पर सभी की निगाहें थी। विलय किया बजट कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब, रेलतंत्र बेसहारा तो नहीं होगा, इस तरह की कई शंका–आशंका रेल यात्रियों के मन में तैर रही थी। लेकिन सरकार ने सभी के मन को भांप कर रेल बजट कुल मिलाकर उनके मुताबिक ही पेश किया। सबसे अच्छा फैसला मानव रहित क्रॉसिंगों को समाप्त करने का रहा। सरकार का मानव रहित क्रॉसिंगों को समाप्त करने का फैसला जनसरोकारी कहा जाएगा। इससे कई लोगों की जाने बच सकेंगी। बजट के मुताबिक पूरे भारत में 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म कर दिए जाएंगे। 92 साल पुरानी रेल बजट परंपरा को खत्म कर उसे आम बजट में विलय करने के बाद बुधवार को वित मंत्री अरूण जेटली ने पहला सम्मलित बजट पेश किया। रेल नेटवर्क के लिहाज से फिलहाल उम्मीद के मुताबिक बजट पेश किया। रेल सुरक्षा और उसकी बुनियादी ढांचे को दुरूस्त करने पर जोर दिया गया है। दरअसल सभी को इस बात का इंतजार था कि विलय के बाद आखिर रेलवे का ख्याल कैसे रखा जाएगा। क्योंकि रेल बजट खत्म करने के बाद रेलवे बेसहारा हो गया था। केंद्र सरकार ने अपने बजट में 2017 के लिए रेल नेटवर्क को और मजबूत करने के साथ रेल यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष पहल की तस्वीर पेश की है। करीब दो हजार करोड़ रूपये का सुरक्षा कोष, नई पटरियां बिछाने और स्टेशनों के पुनर्विकास और उनका आधुनिकरण करने पर जोर दिया गया है। रेल पटरियों से उतरने की कई घटनाओं के बाद एक लाख करोड़ रूपये के सुरक्षा कोष का अलग से प्रावध ाान करना रेल सुरक्षा के हित में माना जा रहा है। आम सहूलियतों की बात करें तो आईआरसीटीसी से ई–टिकट पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इस तरह ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेंगा। इसी के साथ रेलवे को लेकर और भी कई बड़ी घोषणांए की गई है। बजट में की गई बेहतरीन योजनाओं में रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ का फंड आवंटित सबसे अच्छा है। इसके अलावा पांच सौ रेलवे स्टेशन अपाहिजों की सुविधा के मुताबिक होंगे। सात हजार रेलवे स्टेशन सोलर उर्जा से लैस होंगे, पांच सौ किलोमीटर नई रेल लाइन बनाई जाएंगी। साथ ही पूरे भारत में 2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म कर दिए जाएंगे। पर्यटन और तीर्थ के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरु की जाएंगी, रेल में यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होगी, इसके अलावा रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए की कुल पूंजी और विकास संबंधी व्यय होगी। यह ऐसी योजनाएं है जिसका सरोकार आम जन से होगा। पेश किए गए बजट में वित वर्ष में रेलवे नेटवर्क को सुधार के विशेष एजेंडे में शामिल किया गया है। लोगों की आम बजट से ज्यादा इस बार रेल बजट पर ज्यादा नजरें थी। वित मंत्री ने सभी को साधने की कोशिश की है। इस बात का इल्म सरकार को भी था कि पूरे देश की नजरे रेलवे बजट पर रहेंगी। हाल ही में कई रेल दुर्घटनाएं हुई जिसमें सैकड़ों रेल यात्रियों ने अपनी जाने गवाईं। अधिकतर घटनाएं पटरियों से उतरने को लेकर हुई, पूरे रेल नेटवर्क की पटरियों का आध ुनिकरण व उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की पहल की गई है। रेल पटरियों की मजबूती के लिए मुकम्मल परियोजनाओं और उसके प्रारूपों को विशेष एजेंडे में शामिल करने की बात कही गई है। नई रेल लाइनों का विकास, लाइनों का दोहरीकरण, स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा उन्नयन आदि शामिल किया गया हैं। वित मंत्री द्वारा पेश बजट में रेलहित व सुधार के लिए 2017–18 में विकास, प्राधिकरण के गठन की घोषणा सबसे अच्छी पहल समझी जाएगी। यह पहल रेल नेटवर्क के विनियामक का काम करेगी। इसके अलावा उच्च गति रेल प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक एंव अन्य निदेशकों के चयन के साथ इस प्राधिकरण के गठन की घोषणा भी की गई है। वित मंत्री ने बजट के जरिए रेल महकमे को अपने आतंरिक स्त्रोतों से धन जुटान करने को कहा है। उनका कहना भी कई संदर्भों में उचित है, जब तक रेलवे राजस्व बढ़ाने के उपाय नहीं खोजेगा, तब तक हालात ज्यादा ठीक नहीं हो सकते। पिछले तीन माह के भीतर चार बड़ी रेल दुर्घनाए हुई है उन घटनाओं ने केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही वजह है कि बजट में सबसे ज्यादा रेल सुरक्षा उपकरणों पर ध्यान देने की बात कही गई है। देश के चुनिंदा पच्चीस रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर लिफट लगेंगी। ट्रेनों में दिवांगों के लिए विशेष शौचालय स्थापित किए जाएंगे। देश के प्रमुख रेलमार्गों पर ट्रेनों की गति बढ़ाकर 160 से 200 किमोमीटर प्रति घंटा तक करने की महत्वकांक्षी परियोजना की घोषणा की गई है।

ट्रम्प की नीतियों पर नाराजगी ठीक नहीं

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसे फैसले लेने शुरू किये हैं जिनपर लोग नाराजगी दिखा रहे हैं। उन्होंने आधा दर्जन मुस्लिम देशों के शरणार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए एच–1 बी वीजा विधेयक पेशकर दिया। श्री ट्रम्प ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा की कई नीतियों को पलट दिया है। यह सब उन्होंने अपने उन वादों के तहत ही किया है जो चुनाव से पूर्व जनता से किये थे। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को सर्वशक्ति सम्पन्न बनाने की बात कहते रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद का कड़ा विरोध किया है और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों पर भी कड़ाई से पेश आने की बात कही। इसका असर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद को नजरबंद कर दिया गया। हाफिज सईद ने भारत पर आतंकवादी हमले करवाए थे और उस पर कार्रवाई के लिए भारत ने कई तरह से दबाव डाला लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ट्रम्प के एक कदम ने ही पाकिस्तान सरकार के होशोंहवाश ठीक कर दिये। अब अमेरिका की वीजानीति में परिवर्तन की वजह से भारतीय पेशेवरों की नौकरी पर संकट नजर आ रहा है तो भारत में भी श्री ट्रम्प की आलोचना होने लगी लेकिन क्या ट्रम्प की नीतियों पर इस प्रकार की त्वरित प्रतिक्रिया ठीक है? अपने देश के हित में काम करना अमेरिका के राष्ट्रपति का दायित्व है और उस दायित्व को अगर श्री ट्रम्प निभा रहे है तो इसमें अनुचित क्या है।

श्री डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कई विपरीत बातें उसी समय से कही जा रही हैं जब वह हिलेरी क्लिंटन के प्रमुख प्रति द्वन्द्वी बन गये थे। महिलाओं के बारे में ट्रम्प के बयान ने अमेरिका की महिलाओं को सड़क पर उतरने को बाध्य कर दिया था और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तीन दिन बाद ही न्यूयार्क में लाखों लोगों नें जिनमें विशेष रूप से महिलाएं शामिल थीं, प्रदर्शन किया था। इसके बाद श्री ट्रम्प ने धमाकेदार कदम उठाते हुए इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के मुसलमानों को शरणार्थी के रूप में अमेरिका आने से रोक दिया।

मुसलमानों के अमेरिका प्रवेश पर पाबंदी तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी 2011 में लगायी थी। यह वह समय था जब न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर आतंकवादी हमला हुआ था और हजारों लोग मारे गये थे। इसके बाद बराक ओबामा ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ी। अमेरिका ने अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर धुसकर मार गिराया लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादियों की नर्सरी तैयार होने के बावजूद कोई कठोर कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान को अमेरिका से लाखों डालर की मदद आतंकवाद रोकने के नाम पर बराक ओबामा सरकार देती रही जबकि भारत ने कई बार कहा कि अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता का दुरूपयोग करते हुए पाकिस्तान अपने यहां पनप रहे आतंकवादियों की मदद करके भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करवाता है। भारत के कहने के बावजूद न तो अमेरिका ने अपने हाथ आर्थिक मदद के लिए रोके और न पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने सात मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को अमेरिका में आने से रोक दिया तो पाकिस्तान के कान खड़े हो गये। उन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान का नाम भले ही नहीं शामिल है लेकिन श्री ट्रम्प ने यह भी कह रखा है कि आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले मुल्कों के खिलाफ कठोर कदम उठाये जाएंगे। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद की नजरबंदी को इसी धमकी के मद्देनजर देखा जाना चाहिए।

पूर्व वर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी डोनाल्ड ट्रम्प के कदमों का विरोध किया है। हालांकि श्री ओबामा का विरोध करना अमेरिकी संस्कृति के विपरीत है। उन्हें याद होना चाहिए कि जब बराक ओबामा ने राष्ट्रपति रहते अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश की नीतियों को उलट दिया था और उनकी आलोचना भी की थी तब भी जार्ज डब्ल्यू बुश ने बराक ओबामा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। श्री बराक ओबामा को इसलिए भी चुप रहना चाहिए क्यों कि श्री ट्रम्प को अमेरिका की जनता ने राष्ट्रपति चुना है। इसके साथ ही श्री ओबामा के ज्यादा चिंता जताने से उनका पाखंड, विशेष रूप से आतंकवाद को लेकर, सामने आ जाएगा।

पाकिस्तान के खिलाफ ही श्री ओबामा ने कौन सा बड़ा कदम उठाया जबकि ओसामा बिन लादेन वहीं छिप कर रह रहा था। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि ओसामाबिन लादेन पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और सेना के बिना जानकारी के रह रहा था? बल्कि कहा तो यही जाता है कि सेना से ही उसे सुरक्षा भी मिल रही थी, ठीक उसी तरह जैसे भारत के मोस्टवान्टेड माफिया डान दाउद इब्राहीम को करांची में रखा जा रहा है। भारत सबूत भी दे रहा लेकिन पाकिस्तान बराबर झूठ बोल रहा है। अमेरिका में श्री बराक ओबामा ने यदि अपनी बयान बाजी से हटकर कुछ किया होता तो सीरिया और यमन–तुर्की में आज ये हालात न होते।

अब डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने एच–1 बी वीजा विधेयक पेश किया है। यह वीजा अर्हता प्राप्त पेशेवर को दिया जाता है। इसी के आधार पर अमेरिका में कंपनिया हर साल हजारों पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय आईटी कंपनियों की एच–1 बी वीजा में 86 फीसदी हिस्सेदारी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय पेशेवरों पर नौकरी का संकट है। एच–1 बी वीजा धार को 80 हजार डालर तक वेतन मिलता है और 65 हजार लोगों को इसी वीजा के तहत नौकरी मिली हुई है। अमेरिका में 65 फीसद भारतीय इस बीजा को प्राप्त किये हैं। एक अनुमान के अनुसार एक लाख से ज्यादा भारतीय एच–1 बी वीजा के तहत अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। इस वीजा को थोड़ा कठोर बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का विध ेयक पारित हो जाता है तो अमेरिका में कंपनियां एच–1 बी वीजा देकर आसानी से नौकरी नहीं दे सकेंगी। कैलिफोर्निया के सांसद लोफग्रेन के अनुसार हाई स्किल्ड इंटिग्रिटी एण्ड फेयरनेस ऐक्ट–2017 (उच्चकुशल निष्ठा व निष्पक्षता अधिनियम) पेशेवर को 1.30 लाख डालर से अधिक के वेतन पर ही नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे वीजा धारक का न्यूनतम वेतन 68 हजार डालर है। इससे एच–1 बी वीजा धारकों को अच्छा वेतन मिलेगा और यह तो स्वाभाविक है कि अधिक प्रतिभा वाले का सम्मान होना ही चाहिए। भारतीय लोगों की प्रतिभा पर संदेह नहीं किया जा सकता और अब उन्हें अमेरिका के लोगों की प्रतिभा से सीधी प्रतियोगिता करनी है। अभी तक आई टी कंपनियों को भारत से सस्ते स्किल्ड मिल जाते थे। अमेरिका के लोग ज्यादा वेतन मांगते थे और कम वेतन पाने वाले भारतीयों में हीन भावना भी रहती होगी।इस लिए भारतीय लोगों की प्रतिभा और उनकी अमेरिकियों से बराबरी के नजरिए से देखा जाए तो ट्रम्प सरकार का यह अधिनियम अच्छा ही माना जाएगा। भारतीय अर्थ व्यवस्था पर इसका सीमित असर जरूर पड़ा है और शेयर बाजार में भारतीय आई टी कंपनियों के शेयर नीये आ गये लेकिन अमेरिका में भारतीय आई टी कंपनियों का कारोबार प्रभावित नहीं होगा।

संत वैलेन्टाइन को सच्ची श्रद्धाजंली देने के लिए 14 फरवरी 'वैलेन्टाइन दिवस' को 'पारिवारिक एकता दिवस' के रूप में मनायें!

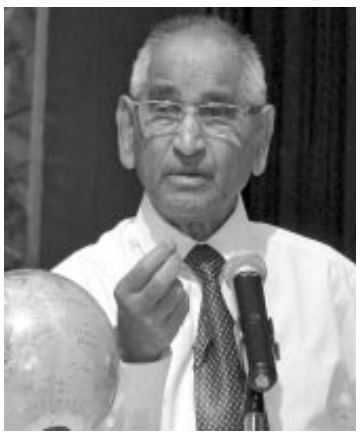

–डॉ0 जगदीश गांधी

(1) 'वैलेन्टाइन दिवस' के वास्तविक, पवित्र एवं शुद्ध भावना को समझने की आवश्यकताः–

संसार को 'परिवार बसाने' एवं 'पारिवारिक एकता' का संदेश देने वाले महान संत वैलेन्टाइन के 'मृत्यु दिवस' को आज जिस 'आधुनिक स्वरूप' में भारतीय समाज में स्वागत किया जा रहा है, उससे हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता प्रभावित हो रही है। संत वैलेन्टाइन ने तो युवा सैनिकों को विवाह करके परिवार बसाने एवं पारिवारिक एकता की प्रेरणा दी थी। इस कारण अविवाहित युवा पीढ़ी का अपने प्रेम का इजहार करने का 'वैलेन्टाइन डे' से कोई लेना–देना ही नहीं है। आज वैलेन्टाइन डे के नाम पर समाज पर बढ़ती हुई अनैतिकता ने हमारे समक्ष काफी असमंज्स्य तथा सामाजिक पतन की स्थिति पैदा कर रखी है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण आज लड़कियों तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराध, छेड़छाड़, अश्लीलता, बलात्कार, हत्या आदि जैसी जघन्य घटनायें लगातार बढ़ती ही जा रहीं हैं।

(2) विवाह के पवित्र बन्धन को 'वैलेन्टाइन दिवस' पूरी तरह से स्वीकारता एवं मान्यता देता है :–

'वैलेन्टाइन डे' का दिन हमें सन्देश देता है कि अविवाहित स्त्री–पुरूष के बीच किसी प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं होना चाहिए। विवाह के पवित्र बन्धन को 'वैलेन्टाइन डे' पूरी तरह से स्वीकारता एवं मान्यता देता है। आज महान संत वैलेन्टाइन की मूल, पवित्र एवं शुद्ध भावना को भुला दिए जाने के कारण यह महान दिवस मात्र युवक–युवतियों के बीच रोमांस के विकृत स्वरूप में देखने को मिल रहा है। वैलेन्टाइन डे को मनाने के पीछे की जो कहानी प्रचलित है उसके अनुसार रोमन शासक क्लाडियस (द्वितीय) किसी भी तरह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह संसार की सबसे ताकतवर सेना को बनाने के लिए जी–जान से जुटा था। राजा के मन में स्वार्थपूर्ण विचार आया कि विवाहित व्यक्ति अच्छे सैनिक नहीं बन सकते हैं। इस स्वार्थपूर्ण विचार के आधार पर राजा ने तुरन्त राजाज्ञा जारी करके अपने राज्य के सैनिकों के शादी करने पर पाबंदी लगा दी।

(3) महान संत वैलेन्टाइन के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रकट करने के लिए मनाया जाता था 'वैलेन्टाइन दिवस' :–

रोम के एक चर्च के पादरी महान संत वैलेन्टाइन को सैनिकों के शादी करने पर पाबंदी लगाने संबंधी राजा का यह कानून ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध प्रतीत हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि युवा सैनिक विवाह के अभाव में अपनी शारीरिक इच्छा की पूर्ति गलत ढंग से कर रहे हैं। सैनिकों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए पादरी वैलेन्टाइन ने रात्रि में चर्च खोलकर सैनिकों को विवाह करने के लिए प्रेरित किया। सम्राट को जब यह पता चला तो उसने पादरी वैलेन्टाइन को गिरतार कर माफी मांगने के लिए कहा अन्यथा राजाज्ञा का उल्लघंन करने के लिए मृत्यु दण्ड देने की धमकी दी। सम्राट की धमकी के आगे संत वैलेन्टाइन नहीं झुके और उन्होंने प्रभु निर्मित समाज को बचाने के लिए मृत्यु दण्ड को स्वीकार कर लिया। संत वैलेन्टाइन की मृत्यु के बाद लोगों ने उनके त्याग एवं बलिदान को महसूस करते हुए प्रतिवर्ष 14 फरवरी को उनके 'शहीद दिवस' पर उनकी दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थनायें आयोजित करना प्रारम्भ कर दिया। इसलिए ऐसे महान संत के 'शहीद दिवस' पर खुशियां मनाकर उनकी भावनाओं का निरादर करना सही नहीं है।

(4) वैलेन्टाइन डे को 'आधुनिक' तरीके से मनाना भावी पीढ़ी के प्रति अपराध :–

'वैलेन्टाइन डे' मनाने को तेजी से प्रोत्साहित करने के पीछे छिपी एकमात्र भावना धन कमाना अर्थात 'वैलेन्टाइन डे' कार्डो की ब्रिकी का एक बड़ा बाजार विकसित करना, फुहड़ डान्सों तथा मंहगे होटलों में डिनर के आयोजनों की प्रवृत्तियों को बढ़ाकर अनैतिक ढंग से अधिक से अधिक लाभ कमाने वाली शक्तियां इसके पीछे सक्रिय हैं। विज्ञापन के आज के युग में वैलेन्टाइन बाजार को भुनाने का अच्छा साधन माना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपना बाजार बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें युवाओं से बेहतर ग्राहक कहीं नहीं मिल सकता। अतः 'वैलेन्टाइन डे' आधुनिक तरीकों से मनाने को प्रोत्साहित करना भावी पीढ़ी एवं मानवता के प्रति अपराध है। अन्तिम विश्लेषण यह साफ संकेत देते हैं कि 'वैलेन्टाइन डे' के आधुनिक स्वरूप का भारतीय समाज एवं छात्रों में किसी प्रकार का स्वागत नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मात्र सस्ती प्रेम भावनाओं को प्रदर्शित करने की छूट कम उम्र में छात्रों को देकर उनकी अनैतिक वृत्ति को बढ़ावा देता है।

(5) परिवार, स्कूल एवं समाज को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित करें :–

हम संत वैलेन्टाइन के इन विचारों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि विवाह के बिना किसी स्त्री–पुरूष में अनैतिक संबंध होने से समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाएगी और समाज ही भ्रष्ट हो जाएगा। इस समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय है, बच्चों को बचपन से ही भौतिक, सामाजिक, मानवीय तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार की संतुलित शिक्षा देकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। किसी भी बच्चे के लिए उसका परिवार, स्कूल तथा समाज ये तीन ऐसी पाठशालायें हैं जिनसे ही बालक अपने सम्पूर्ण जीवन को जीने की कला सीखता है। इसलिए यह जरूरी है कि परिवार, स्कूल तथा समाज को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित किया जाये। एक स्वच्छ व स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व के बच्चों की सुरक्षा व शांति के लिए आवाज उठायें और पूरे विश्व के बच्चों तक संत वैलेन्टाइन के सही विचारों को पहुँचायें जिससे प्रत्येक बालक के हृदय में ईश्वर के प्रति, अपने माता–पिता के प्रति, भाई–बहनों के प्रति और समाज के प्रति भी पवित्र प्रेम की भावना बनी रहे।

(6) परिवार, विद्यालय तथा समाज से मिली शिक्षा ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती हैः–

दिल्ली गैंगरेप कांड जैसी बढ़ती घटनायें चारित्रिकता, नैतिकता, कानून व जीवन मूल्यों की शिक्षा के अभाव में राह भटक गये लोगों के कारण ही हो रहीं हैं। वास्तव में किसी भी मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को तीन प्रकार के चरित्र निर्धारित करते हैं। पहला प्रभु प्रदत्त चरित्र, दूसरा माता–पिता के माध्यम से प्राप्त वांशिक चरित्र तथा तीसरा परिवार, स्कूल तथा समाज से मिले वातावरण से विकसित या अर्जित चरित्र। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरित्र तीसरा अर्थात् 'अर्जित चरित्र' होता है। बालक को जिस प्रकार की शिक्षा परिवार, विद्यालय तथा समाज से मिलती है वैसा ही उसका चरित्र निर्मित हो जाता है। इसलिए आज संसार में बढ़ते अमानवीय कृत्य जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय आदि शैतानी सभ्यता इन्ही तीनों क्लासरूमों से मिल रही उद्देश्यविहीन शिक्षा के कारण ही है।

(7) 'वैलेन्टाइन डे' को 'पारिवारिक एकता दिवस' के रूप में मनाने की प्रतिज्ञा लें :–

आइये, वैलेन्टाइन डे पर हम सभी लोग यह प्रतिज्ञा ले कि हम अपने मस्तिष्क से भेदभाव हटाकर सारी मानवजाति से प्रेम करेंगे व समानता की भावना पैदा करेंगे। भारत की संस्कृति व सभ्यता ही आज की जरूरत है। प्रेम तो ईश्वर से होना चाहिए क्योंकि यही जीवन का शाश्वत सत्य है। अगर ईश्वर से हमारा तार कट गया तो कोई अन्य प्रेम हमें नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमें वैलेन्टाइन डे पर भाई–बहन का प्रेम, दादा–दादी का प्रेम, माता–पिता का प्रेम, गुरूजनों का प्रेम भी शामिल करना चाहिए तभी हम इस त्योहार का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। संत वैलेन्टाइन के प्रति सच्ची श्रद्धा यही होगी कि हम 14 फरवरी 'वैलेन्टाइन डे' को पवित्र भावना से 'पारिवारिक एकता दिवस' के रूप में मनायें और संसार के सभी बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को यह संदेश भेजें कि सभी लोग एक–दूसरे से समान रूप से प्रेम करें, आदर करें, तभी एक आध्यात्मिक विश्व की स्थापना हो सकेगी।

–जय जगत–

चुनाव आते ही जनता के दोनों हाथों में लड्डू!

पहले मुफ्त में लैपटॉप मिला अब स्मार्टफोन मिलेगा...गरीब महिलाओं को खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर वो भी फ्री। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव आते ही राजनीतिक दलों ने जनता पर मुफ्त सौगातों की बरसात कर दी। 5 साल सत्ता में रहने के दौरान जनता को भले ही कुछ हासिल ना हो...लेकिन चुनाव आते ही रेवड़ियां बंटनी शुरू हो जाती हैं। पिछली बार यूपी में लैपटॉप का लॉलीपॉप बांटने वाले अखिलेश इस बार भी जनता पर मेहरबान हैं। चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर मेधावी छात्रों को इस बार लैपटॉप के साथ फ्री में स्मार्ट फोन देने का भी वादा किया है। लखनऊ से लेकर नोएडा को चमकाने का दावा करने वाले अखिलेश को मालूम है कि अगर जनता को खुश करना है तो उन्हें चुनावी वादों की घूस देनी होगी। युवाओं को स्मार्ट फोन का लालच देने के बाद अखिलेश ने गरीब महिलाओं को मुफ्त में प्रेशर कुकर देने का भी ऐलान कर डाला। अखिलेश के पिटारे में यूपी की गरीब जनता को देने के लिए अभी और भी कुछ बचा था। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को जहां मुफ्त में चावल–गेहूं देने की बात कही वहीं प्राथमिक स्कूल में कुपोषित बच्चों को मुफ्त में एक किलो घी और एक लीटर दूध पाउडर देने का भी ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराए में आधी छूट मिलेगी और तो और 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए हर महीने पेंशन भी मिलेगी। अब जनाब जनता तो जनता ठहरी...अगर उसे मुफ्त में इतनी चीजें मिलें तो फिर उसका मन तो डोलेगा ही। मतदाताओं पर डोरे डालने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता. ..पंजाब में अकाली दल ने भी लगे हाथों लोकलुभावन वादों की झड़ी लगा दी। जिस दाल ने पिछले साल लोगों का दिवाला निकाला दिया था उन्हें अकाली दल ने सत्ता में आने पर 10 रुपए किलो दाल देने का वादा कर डाला....दाल ही नहीं अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों को आटा, चावल और चीनी भी 10 रुपए किलो देने की बात कही। अकाली दल ने अखिलेश की तरह पंजाब में भी गरीबों को मुफ्त में प्रेशर कुकर और गैस कनेक्शन देने का वादा कर डाला। अकाली दल ने 25 रुपए किलो घी देने की बात कह राज्य के गरीब बच्चों को पहलवान बनाने का भी सपना दिखा दिया। 10वीं पास लड़की को मुफ्त में सिलाई मशीन, किसानों को रोजाना 10 घंटे फ्री बिजली, गरीब लड़कियों की शादी पर 51 हजार रुपये का शगुन...अब पंजाब की गरीब जनता को और क्या चाहिए? घोषणा पत्र में जनता को लुभाने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही...आप ने चुनावी घोषणा पत्र में पंजाब में सत्ता में आने पर गरीबों को जहां 5 रुपए में खाना खिलाने का वादा किया वहीं दिल्ली की तर्ज पर 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने का ऐलान किया।

आखिर हम कहां जा रहे हैं. ..इलाके में बेहतर सड़क हो या नहीं, गांव में अस्पताल हो या नहीं, बेरोजगारों को नौकरी हो या नहीं...ये सभी बातें पीछे रह गईं.. .अब नेताओं को लगने लगा है कि जनता को व्यक्तिगत फायदे चाहिए. .तभी तो वो लैपटॉप से लेकर स्मार्ट फोन की बात कर रहे हैं।

वैसे चुनाव में रेवड़ियां बांटने का ये सिलसिला नया नहीं है... दक्षिण में मिक्सी से लेकर रंगीन टेलीविजन सेट बांटने की पुरानी परंपरा रही है और तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि को इसका लाभ भी मिला। 1 रुपए में इडली और 5 रुपए में सांबर–चावल खिलाने वाली श्अम्म्मा कैंटीनश ने जयललिता को इतना लोकप्रिय बना दिया था कि उनकी दोबारा सत्ता में वापसी हो गई थी। साफ है अब जनता के साथ–साथ राजनीतिक पार्टियां भी होशियार हो गई हैं...राजनीतिक दलों को पता है...पैसा जनता का है सो टेंशन की कोई बात नहीं। बस लुटा दो।

शिवपाल को नुकसान पहुंचा सकती थी 'चुप्पी'

लखनऊ। बीते कई दिनों से खामोश दिख रहे शिवपाल यादव मंगलवार को बोले। उन्होंने चुनाव बाद नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। शिवपाल की यह चुप्पी नामांकन के दिन अचानक टूटने के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुलायम के गढ़ इटावा में मंगलवार को शिवपाल अगर चुप रह जाते तो शायद यह उनके लिए खतरनाक हो सकता था। शिवपाल के करीबी समाजवादी नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, ख्ाुद मुलायम समाजवादी पार्टी–कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसे में शिवपाल की चुप्पी से उन्हें बड़ी चुनौती मिल सकती थी। सूत्रों का कहना है कि इटावा में सीएम अखिलेश यादव ने सिर्फ जसवंतनगर विधानसभा में ही शिवपाल यादव के रूप में अपने विधायक को रिपीट किया है। बाकी दो सीटों भरथना और इटावा सदर से दोनों सीटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। इटावा सदर से विधायक रहे रघुराज शाक्य इटावा से सांसद और इस बार विधायक रहे।

जसवंतनगर में यादवों से कुछ कम शाक्य मतदाता है। रघुराज का टिकट काटकर कुलदीप गुप्ता संटू को मौका देने से शाक्य वोटरों में नाराजगी बताई जा रही है। चूंकि बीजेपी ने दुर्गेश शाक्य को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है, इससे शिवपाल को नुकसान हो सकता था। यही वजह है कि शिवपाल ने पहले रघुराज को साथ रखा और नामांकन के दिन उनके समर्थन में भी बोले। इससे जसवंतनगर के शाक्य मतदाताओं में अच्छा संदेश जाएगा और शिवपाल को फायदा मिलेगा।

शिवपाल जिस जसवंतनगर सीट से मैदान में ताल ठोंकने जा रहे हैं, वह उन्हें समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से ही विरासत में मिली है। मुलायम यहां से 1967 से लेकर 1993 तक विधायक रहे थे। 1993 में यह सीट उन्होंने शिवपाल यादव को सौंप दी थी। शिवपाल तब से लगातार चार बार विधायक चुने गए। इटावा में अब भी पार्टी में मुलायम का ही अक्स देखा जाता है। लोग मानते हैं कि मुलायम और उनके बाद शिवपाल ही इटावा के लोगों से मिलते और उनकी बात सुनते हैं।

कांग्रेस गठबंधन के विरोध में बयान आने और अपने लोगों को कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने के मुलायम के बयान के बाद से इटावा में यह संदेश फैलने लगा था कि मुलायम काफी तकलीफ में हैं। वहीं शिवपाल और मुलायम के करीबी अंबिका, नारद राय जैसे दिग्गजों के बीएसपी और तमाम और विधायकों के लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लेने के बाद यह भी लगने लगा था कि शिवपाल यादव ख्ाुद तो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया।

शिवपाल ने भी चुप्पी तब तोड़ी जब पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव बोले। पहले ख्ाुद शिवपाल यह नहीं समझ पा रहे थे कि मुलायम उनके साथ ख्ाुलकर हैं या नहीं। दरअसल मुलायम भी पहले सीएम अखिलेश यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कह रहे थे। वह तब बदले जब दिल्ली पहुंच गए। 29 जनवरी को जब गठबंधन का ऐलान हो रहा था, उसी दिन वह दिल्ली गए। दिल्ली जाते वक्त ही उन्होंने फ्लाइट में एक पत्रकार से कहा था कि वह 12 फरवरी से अखिलेश के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पर दिल्ली में कुछ लोगों से मिले, उन्होंने गठबंधन के विरोध में बयान देना शुरू कर दिया।

प्रमाण सहित इतिहास ही सार्थक : केशरीनाथ

इलाहाबाद। इतिहास तभी सार्थक माना जाता है, जब वह प्रमाण सहित हो। प्रमाणों का संकलन शोध के बिना संभव नहीं होता। ोहदू हॉस्टल में प्रो. बीएनएस यादव की कृति सोसायटी एंड कल्चर इन नार्दर्न इंडिया इन ट्वेल्थ सेंचुरीश का विमोचन करते हुए यह विचार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी ने व्यक्त किए। इसके अलावा उन्होंने माघ मेला के महात्म्य पर आयोजित एक गोष्ठी में भी हिस्सा लिया।विमोचन सत्र की अध्यक्षता न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय ने की। मुख्य अतिथि राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि इतिहास का काम सतह के नीचे दबे सत्य को उजागर करना भी है। न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय ने कहा कि अपने देश के इतिहास को ठीक से जाने बिना अपनी संस्कृति का बोध नहीं हो सकता। संयोजक प्रो. एपी ओझा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर इविवि कला संकाय के डीन प्रो. केएस मिश्र, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. आरकेपी सिंह, कुलानुशासक प्रो. हर्ष कुमार, प्रो. एचएन दूबे, प्रो. यूसी चटोपाध्याय, प्रो. हेरंब चतुर्वेदी, डॉ. राजेश मिश्र, अमरेंदु सिंह, पंकज कुमार आदि थे।

उधर, इलाहाबाद वेलफेयर ग्रुप की ओर से माघ मेला महात्म्य पर एक गोष्ठी का आयोजन बैरहना में हुआ। जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि प्रयाग में बड़े–बड़े विद्वान, राजा, दार्शनिक, विचारक आए। उन्होंने अपनी पुस्तकों में प्रयाग के महत्व का वर्णन किया है। विशिष्ट अतिथि पं. रामनरेश त्रिपाठी ने प्रयाग की गंगा–यमुनी संस्कृति को बचाने का आह्वान किया। संयोजक बब्बू राम द्विवेदी ने भी ग्रुप के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।इस मौके पर पदुम जायसवाल, शिवेंद्र मिश्र, राजेश शर्मा, प्रमोद जायसवाल, राकेश शर्मा, विजय व्यास, लालजी शुक्ल, विजय मिर, योगेंद्र शुक्ल, दिनेश तिवारी, देवेंद्र मिश्र, शशांक शेखर पांडेय, कमलेश केसरवानी आदि मौजूद रहे।

अवैध कब्जेदारों से मुक्त होगी श्रम विभाग की कॉलोनी

रायबरेली। बेशकीमती भूमि पर बनी श्रम विभाग की कॉलोनी पर सालों से काबिज अवैध कब्जेदारों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इस कॉलोनी का निर्माण आइटीआइ के कर्मचारियों को रहने के लिए किया गया था। नौकरी छोड़ने के बाद भी तमाम कर्मचारी यहां जमे हुए हैं, वहीं बाहरी लोगों ने भी आवासों पर अपना कब्जा जमा लिया है। श्रम सहायक श्रमायुक्त ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। कॉलोनी का सर्वे कराने के लिए अमर श्रमायुक्त लखनऊ को पत्र लिखा गया है, ताकि कब्जेदारों का पता लग सके।

जिले में इंडियन टेलीफोन इंड्रस्टीज की स्थापना के बाद वहां काम करने वाले कर्मचारियों को आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने फैक्ट्री के निकट ही कॉलोनी का निर्माण कराया था। यहां 220 आवास बने हैं। आवासीय सुविधा के साथ ही यहां पर चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती थी। इसके लिए बाकायदे स्वास्थ्य टीम की तैनाती थी।

कोई हाईस्कूल पास तो कोई विधि का जानकार

उन्नाव। जिले की छह विधानसभा के रण में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही योद्धाओं को लेकर चल रही सारी अटकलें ख्त्म हो गई हैं। इस बार के चुनावी रण में अधिकतर उम्मीदवार शिक्षित हैं। उनमें भी कई कानूनविद है तो कोई कंप्यूटर साइंस का जानकार और किसी के पास प्रबंधन की डिग्री है। मजे की बात तो यह है, अधिकतर प्रत्याशियों की आजीविका का साधन खेती है। हालांकि वह वाहनों के काफिलों के साथ चलने वाले राजनीति के धाकड़ हैं।

162–बांगरमऊ विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे कुलदीप ोसह सेंगर इंटरमीडिएट तक शिक्षित हैं और मुख्य कारोबार कृषि है। इस कृषि के सहारे ही उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसी विधानसभा से उतरे उम्मीवार सपा के मौजूदा विधायक बदलू खां इंटरमीडिएट भी तक ही शिक्षित हैं। कारोबार के साथ साथ कृषि भी उनकी आय का जरिया है। बसपा उम्मीदवार इरशाद खान स्नातक तक शिक्षित हैं और राजनीति के अलावा व्यापार और कृषि इनकी आय का जरिया है।

163–सफीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री सुधीर रावत बीएससी एलटी होने के साथ ही पेशे से शिक्षक हैं। इसी सीट से बसपा उम्मीदवार रामबरन स्नातक हैं और राजनीति के अलावा इनका मुख्य व्यवसाय कृषि हैं। वहीं भाजपा से प्रत्याशी बने बंबालाल दिवाकर ने तमिलनाडू से स्नातक किया। देश विदेश में इनका कारोबार है। अब राजनीति में सक्रिय हुए हैं।

164–मोहान विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राधेलाल रावत परास्नातक के साथ एलएलबी हैं। राजनीति के अलावा इनका मुख्य काम कृषि है। यहीं से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार रावत एमए एलटी हैं और राजनीति के अलावा पेशे से शिक्षक हैं। यहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी बने भगवान दास कठेरिया आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक के अलावा क्षेत्राधिकारी पुलिस के पद से सेवानिवृत्त हुए।

165–उन्नाव सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक पंकज गुप्ता बीएससी गणित से हैं। राजनीति के अलावा व्यापार व कृषि इनकी आय का जरिया है। इसी सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी मनीषा दीपक जूनियर हाईस्कूल तक शिक्षित हैं। विरासत में मिली राजनीति के अलावा आय का जरिया व्यापार और कृषि है। जबकि बसपा से उम्मीदवार पंकज त्रिपाठी परास्नातक हैं। राजनीति के अलावा लंबा चौड़ा कारोबार व कृषि आय का जरिया है।

166–भगवंत नगर विधानसभा हृदय नारायण दीक्षित एमए अर्थशास्त्र से हैं। जबकि राजनीति की लंबी पारी के अलावा कृषि और पत्रकारिता इनका पेशा है। इसी सीट से बसपा प्रत्याशी शशांक शेखर ोसह सनी बीबीए (बैचलर आफ बिजनेस एडमिनस्ट्रेशन) यानी प्रबंधन की डिग्री धारक के अलावा कांस्ट्रक्सन का कारोबार करते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अंकित ोसह परिहार बीटेक हैं और राजनीति के अलावा व्यापार इनकी आय का जरिया है। जबकि लोकदल प्रत्याशी कृपाशंकर ोसह एमए एलएलबी शिक्षित होने के साथ ही वकालत पेशे से जुड़े हैं।

167–पुरवा विधानसभा से सपा प्रत्याशी विधायक उदयराज यादव बीए एलएलबी हैं साथ ही कृषि और व्यापार करते हैं। इसी सीट से बसपा प्रत्याशी अनिल ोसह मऊ से इंटरमीडिएट तक शिक्षित हैं और पत्नी और स्वयं कांस्ट्रक्सन के कारोबार से राजनीति में आने से पहले से करते हैं। जबकि भाजपा प्रत्याशी उत्तम चंद्र लोधी उर्फ राकेश लोधी ने कहा कि एमए एलएलबी डिग्री धारक विधि के जानकार तो हैं ही साथ ही रियल स्टेट का कारोबार करते हैं।

रामगंगा नदी में मिला युवक का शव

शाहजहांपुर । रामगंगा नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव तीन दिन पुराना है। शव की शिनाख्त नहीं हो पायी है। थाना क्षेत्र के मऊ जंगल में रामगंगा नदी के किनारे जानवर चराने गए लोगों ने नदी के किनारे शव तैरता देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबकि अज्ञात युवक की उम्र 25 वर्ष है। वह शर्ट व पैंट पहने हुए है। मगर पैरों में जूते व चप्पल नहीं है। पुलिस ने तलाशी ली, मगर उसके पास से कुछ नहीं मिला। लोगों ने बताया कि सोमवार को राजेपुर के पास नदी में शव देखा गया था। एसओ ने बताया कि शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कराया गया। लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पायी है।

क्या ऐसे ही गढ़ा जायेगा देश का भविष्य?

– अजय कुमार श्रीवास्तव

एक परिवार, समाज और देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा सरकार ने देश के 6 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार तो प्रदान कर दिया किन्तु इस अधिकार के अन्तर्गत देश के गाँव–गाँव में रहने वाले प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले? इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हम सभी जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है। यहां की अधिकांश आबादी इन्हीं गाँवों में ही निवास करती है। इन्हीं गाँवों की स्कूली शिक्षा पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था 'प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन' द्वारा हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर–2016) के अनुसार शिक्षा पर भारी खर्च के बाद भी ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों (जहां कि निःशुल्क शिक्षा के साथ ही सरकार उन्हें दोपकर का खाना, किताबें, कापियां, छात्रवृत्ति और बैग तक मुत दे रही है।) की स्थिति में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला है।

देश के 589 ग्रामीण जिलों के 15,630 सरकारी स्कूलों तथा 3 से 16 आयु वर्ग के 562,305 बच्चों पर किये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित एन्युअल स्टेट्टस ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट 2016 बताती है कि देश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 के 57.5 प्रतिशत बच्चे कक्षा 1 स्तर का पाठ नहीं पढ़ सके, 72.3 प्रतिशत बच्चे दो अंकों वाले घटाव के सवाल को हल नहीं कर सके और 68.00 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के सामान्य शब्द नहीं पढ़ सके। इसी रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 5 के 74.00 प्रतिशत बच्चे साधारण भाग के सवाल हल नहीं कर सके। रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 8 के 56.7 प्रतिशत बच्चे 3 अंक का 1 अंक से भाग वाले सवाल को हल नहीं कर सके, 26.9 प्रतिशत बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सके और 54.8 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य नहीं पढ़ सके। वास्तव में यह रिपोर्ट ग्रामीण भारत की प्राथमिक शिक्षा पर अत्यन्त ही चिंताजनक और झकझोरने वाली तस्वीर पेश करती है जबकि प्राथमिक शिक्षा ही किसी व्यक्ति के जीवन की वह नींव होती है, जिस पर उसके संपूर्ण जीवन का भविष्य तय होता है। यूनेस्को की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत में बच्चों को शिक्षा की उपलब्धता आसान हुई है। लेकिन गुणवत्ता का सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है और स्कूल जाने वाले बच्चे भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

न्यू एजुकेशन पालिसी का ड्राट तैयार करने के लिए पूर्व में बनी कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम ने भी अपने एक साक्षात्कार में यह स्वीकार किया है कि जब से देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया है तब से शिक्षा की गुणवत्ता में 25 प्रतिशत गिरावट आ गई है। इन सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर चिन्ता व्यक्त करते हुए वर्ष 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी मद से वेतन लेने वाले सभी अधिकारियों एवं अधिकारियों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आदेश तक पारित करना पड़ा था। इस निर्णय के पीछे एक सीधी धारणा थी कि सत्तासीन वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों मे पढ़ेंगे तो वहाँ के शैक्षिक स्तर में भी उन्नति होगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर के संबंध में समय–समय पर मीडिया में दिखाई गई रिपोर्टें देश के सरकारी स्कूलों की बहुत ही भयानक तस्वीर प्रस्तुत करतीं हैं।

शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के साथ ही सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि उनके गाँव–गाँव में चलने वाले सरकारी स्कूलों एवं निजी स्कूलों की गुणवत्ता कैसे बढ़े? कैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिशिचित की जाये? कैसे इन सरकारी शिक्षकों की जवाबदेही तय की जायें? कैसे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जाये? इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सम्मानजनक रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुर्सी–मेज की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई एवं शौचालय आदि की व्यवस्था कैसे की जाये? इन दिशाओं में ठोस कदम उठाने की बजाय सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करके देश के केवल 15 प्रतिशत निजी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक की 25 प्रतिशत सीटों को चंद दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करके देश के बच्चों के बीच एक भेदभाव की दीवार और भी खड़ी कर दी है।

यह हमारे देश के बच्चों का दुर्भाग्य ही है कि आज हम मंगल ग्रह तक तो पहुंच गये हैं किन्तु आज भी हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे भीषड़ जाड़े और गर्मी के मौसम में टाट पट्टियों पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इन सरकारी स्कूलों के कमरों में पंखे और बल्ब/ट्यूब लाइट तो लगे हैं किन्तु बिजली कनेक्शन के अभाव में यह मात्र शो पीस बनकर रह गये हैं। 28 नवम्बर, 2016 को प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की खराब स्थिति पर सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे वातावरण में न तो शिक्षा दी जा सकती है और न ली जा सकती है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अगर वह स्कूल दुरुस्त नहीं कर सकती तो ये खराब शासन का संकेत है। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह में इलाहाबाद के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और सफाई आदि की कमी दूर करने का आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन हरिजन महिला की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किये।

विश्व बैंक के भारत में क्षेत्रीय निदेशक ओनो रूल का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना चाहिए। दुनिया का इतिहास गवाह है कि विकसित देशों के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकसित देशों में नीतिगत रूप से शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है, पर हमारे देश में शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 28 जून 2016 को यूनिसेफ द्वारा 195 देशों में जारी ''स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2016'' का थीम है 'सभी बच्चों के लिए समान अवसर'। हमारा ऐसा मानना है कि कैशलेस स्कूल वाउचर सिस्टम के माध्यम से हम 'अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग' के प्रत्येक बच्चों को समान व गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं जो कि आरटीई ऐक्ट 2009 का उद्देश्य भी है जिससे इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में सम्मान के साथ सम्मिलित किया जा सकता है और जिसे सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) महत्वकांक्षी एवं भ्रष्टाचार मुक्त योजना के अन्तर्गत लागू किया जा सकता है। स्कूल वाउचर वह कैशलेस व्यवस्था है जिसके माध्यम से देश के कमजोर वर्ग के प्रत्येक बच्चे को एक निश्चित धनराशि का वाउचर उनकी फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जायेगा। इस वाउचर को बच्चे अपने फीस के रूप में अपने पसंद के सरकारी/निजी स्कूल में प्रतिमाह जमा कर दिया करेंगे। सरकारी/निजी स्कूल इन सभी वाउचरों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसे सरकार ने भुगतान हेतु अधिकृत किया होगा, में प्रस्तुत करके वाउचर के बराबर की धनराशि प्राप्त कर लेगा। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई संभावना भी नहीं रहेगी साथ ही इस बाउचर धनराशि को प्राप्त करने के लिए सभी स्कूल अपने स्कूल द्वारा बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्ता को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत् रहेंगे। लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि स्कूल वाउचर देते समय सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रत्येक बच्चे के आधार कार्ड को उनके 'स्कूल वाउचर' से जरूर लिंक करवाये।

इस देश की नीतियों को तय करने वाले लोगों को समझना होगा कि विकास का मतलब केवल जीडीपी में उछाल नहीं है। देश का असली विकास तो तब होगा जब समाज के सभी वर्गों के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, वो चाहे गाँवों में रहता हो, कस्बों में या शहरों में। इसलिए अगर सरकार वास्तव में देश के प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक शिक्षा मिलने के उनके संवैधानिक मौलिक अधिकार के प्रति संवेदनशील है तो सबसे पहले उसे प्रत्येक सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक बच्चे की स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य बनाने के लिए कैशलेस 'स्कूल बाउचर सिस्टम' को सारे देश में लागू करना होगा नहीं तो आने वाले समय में देश के गाँवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली बाल एवं युवा पीढ़ी के साथ ही देश का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है।

मतदाता सांप की बीन की तरह वायदों पर कब तक झूमते रहेंगे

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में असली परीक्षा राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि मतदाताओं की है। विधानसभा चुनाव में तकरीबन 16 करोड़ मतदाताओं को राजनीतिक दलों की पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन की परीक्षा देनी है। उन्हें साबित करना है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को चुनने का पैमाना कितना विवेकसम्मत और तार्किक है। राजनीतिक दल तरह.तरह के प्रलोभनों की दुकानें सजाए बैठे हैं। हर राजनीतिक दल इस वक्त मतदाताओं का हितेषी नजर आ रहा है। मतदाताओं से लोकलुभावन वायदे किए जा रहे हैं। कोई उन्हें मोबाइल बांट रहा है, तो कोई दूसरी तरह के सब्जबाग दिखा रहा है। प्रत्याशियों के चयन में भी भाई.भतीजावाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक को भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में कहना पड़ा कि नेता रिश्तेदारों के लिए टिकट दिए जाने का दबाव नहीं बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद राजनीतिक दलों के नेता अब शायद जाति.धर्म, सम्प्रदाय के नाम पर मतदाताओं का धरुवीकरण नहीं कर पाएं। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि राजनीतिक दल जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसी बुराईयों का सहारा लिए बगैर बाज नहीं आएंगे। मौजूदा हालात के बावजूद मतदाताओं को तय करना है कि वे किसे नेता चुनें। विषेश तौर पर मतदाताओं को निर्णायक फैसला राज्य सरकारों के कामकाज को लेकर देना है। प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर मोदी सरकार भी कसौटी पर उतरेगी। सभी दलों के नेता चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं और फिल्मी सितारों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्षी दल मौजूदा सत्तारूढ़ दलों की कमियों को निशाना बना रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ दल मतदाताओं को विपक्षी दलों के पुराने दागदार इतिहास के साथ प्रदेश में किए गए विकास कार्यों को गिना रहे हैं। हर राजनीतिक दल मतदाताओं को प्रदेश और क्षेत्र के विकास का सुनहरा ख्वाब दिखा रहा है। इनके वायदों से लगता यही है यदि सत्ता में आ गए तो समझो कि प्रदेश में चहुं और विकास होने वाला है। बड़ा सवाल यही है कि क्या मतदाता राजनीतिक दलों के बनाए जाति, धर्म, परिवार के जाल को वोटों की ताकत से काट पाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो जातिवादी और धर्म की जड़ें लोकतंत्र को लीलने की हद तक जा पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट के भय से बेशक अब कोई राजनीतिक दल सीधे इस आधार पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। इसके बावजूद टिकटों का वितरण जाति. धर्म और क्षेत्रवाद के नाम पर किया जा ही रहा है।ऐसे में क्या मतदाता चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। मतदाता सभी चुनावी राज्यों में विकास की नई इबारत लिखने का दावा करने वाले राजनीतिक दलों को पहचान पाएंगे? संकीर्ण सोच से ऊपर उठ कर विवेक सम्मत निर्णय दे पाएंगे? मतदाताओं का पिछला इतिहास देखें तो तस्वीर निराशाजनक ही नजर आती है। इन पांचों ही नहीं देश में हुए दूसरे राज्यों के विधानसभा या दूसरे चुनावों में मतदाता दिग्भ्रम का शिकार रहे हैं। विषेश तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में हालात निराशाजनक ही रहे हैं। मतदाताओं ने सरेआम जाति.धर्म के नाम पर चुनाव मैदान में उतरे विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के हाथों में लोकतंत्र की कमान थमाई है।

ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए

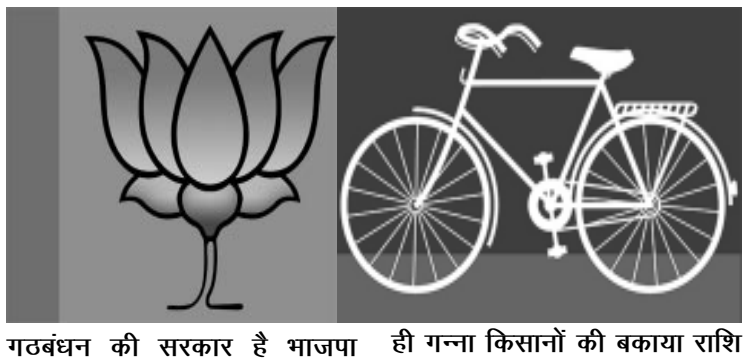

लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ–साथ रोड शो किया। उससे एक दिन पहले ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। चुनाव के समय सभी दल अपना घोषणा पत्र यह कहकर जारी करते हैं कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे इन कार्यक्रमों को लागू करेंगे। इसी तरह यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का तात्पर्य है अखिलेश यादव और उनके समर्थकों की पार्टी का मंतव्य क्योंकि सपा के प्रमुख माने जाने वाले, जिन्हें उनके बेटे अखिलेश यादव ने अब पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया है, श्री मुलायम सिंह ने उस समय भी कांग्रेस का विरोध किया जब राहुल और अखिलेश एक साथ हाथ पकड़कर लखनऊ में रोड शो कर रहे थे। इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र और राहुल–अखिलेश के रोड शो में संयुक्त रूप से क्या कहा जा रहा है, उसे याद रखने की जरूरत है ताकि उचित समय पर उसका जवाब मांगा जा सके।हम थोड़ी देर के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात को मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग दो–तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भगवान, किसान और जवान को केन्द्र बिन्दु में रखा है। भगवान अर्थात अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर का निर्माण कराने का वादा किया गया है लेकिन इसके लिए संविधान के तहत ही काम करने की बात भी कही गयी। कहने की जरूरत नहीं कि भाजपा ने भगवान श्रीराम के प्रति किये गये वादों से सबक लिया है। भाजपा की जब केन्द्र में सरकार नहीं थी तब कहा था कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनी तो अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बन गयी तो कहा गया कि यह तो गठबंधन की सरकार है भाजपा अपने स्तर से कोई फैसला नहीं कर सकती, लिहाजा जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तब श्री रामलला का मंदिर बनाया जाएगा। श्री रामलला ने भाजपा की फिर सुन ली और 2014 में भाजपा की प्रचण्ड बहुमत वाली सरकार बन गयी लेकिन श्री रामलला फटे तिरपाल में ही विराजमान रहे। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से अब उस फटे तिरपाल को हटाया जा रहा है। इसलिए भाजपा ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बहुत सोच समझकर भगवान से वादा किया है। इसी क्रम में भाजपा ने यूपी के 90 फीसद युवाओं को रोजगार या नौकरी दिलाने का वादा किया है। इससे युवाओं को एक उम्मीद मिली कि बेरोजगारी का पहाड़ काफी छोटा हो जाएगा। खास बात यह कि भाजपा ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात नहीं कही लेकिन डिजिटल बनाने का वादा किया है। किसानों को अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही लुभावने आश्वासन मिले हैं। लघु एवं सीमांत किसानों को बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा, फसली ऋण माफ कर दिया जाएगा और सबसे बड़ी राहत गन्ना किसानों को दी गयी है कि फसल बेचने के 14 दिन के अंदर ही भुगतान मिल जाएगा। इतना ही नहीं घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर 120 दिनों अर्थात् चार महीने के अंदर ही गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। भाजपा ने धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का वादा भी किया है। प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रुपये कुंटल है जबकि 800 रुपये में व्यापारी खरीद रहे हैं। इस प्रकार कई वादे किये गये हैं जिन्हें प्रदेश की जनता अपने जहन में रखे और समय पर इसके लिए जवाब भी मांगे।इसी प्रकार हम थोड़े समय के लिए अखिलेश यादव की बात पर भी विश्वास कर लेते हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में प्रदेश की 250 सीटें जीत सकती थी लेकिन अब कांग्रेस का साथ मिल गय है तो तीन सौ सीटों पर जीत मिलेगी। इस प्रकार प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनने की संभावना बन जाती है। यह सरकार भी उसी तरह से मजबूत होगी जैसे श्री अमित शाह ने भाजपा सरकार बनने का आकलन किया है। इसलिए यदि अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में दुबारा सरकार बन गयी तो उनकी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसकी प्रमुख बातों को भी याद रखना पड़ेगा। कांग्रेस ने तो प्रदेश के लिए अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है। सरकार बनने पर वह (कांग्रेस) सरकार में शामिल होगी या बाहर रहकर समर्थन करेगी, यह बाद की बात है लेकिन इतना तो साफ है कि यदि सरकार बनी तो अखिलेश यादव के हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा, तब अगर वे अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो उनसे भी जवाब मांगा जा सकता है।

समाजवादी पार्टी ने 23 जनवरी को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था। सीएम अखिलेश यादव ने दुबारा सरकार बनने पर, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, युवाओं, गरीबों को खास तोहफे देने का वादा किया। गांव वाले याद रखें कि श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि शहरों की तरह गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। फिलहाल शहरों को भी जिस तरह अघोषित कटौती करके बिजली दी जाती है, उस तरह भी गांवों को बिजली मिलने लगे तो गांवों के भाग्य चमक जाएंगे। अखिलेश यादव ने 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने, एक करोड़ लोगों को एक हजार रुपया प्रति माह पेंशन देने, मजदूरों को सस्ता मिड–डे–मील के साथ पूर्व में किये गये वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। कुपोषित बच्चों को एक किलो देशी घी देने का वादा भी किया गया है। किसानों के लिए सपा का वादा पांच साल तक कसौटी पर रहा है और धान की फसल औने–पौने दाम पर बेचने वाले किसानों को फिर से प्रलोभन देना मुश्किल होगा। गांवों की हालत कितनी सुधरी है, यह पता तब चलता है जब आप किसी ऐसे गांव में पहुंचें जहां बिजली नहीं, आने–जाने के रास्ते नहीं। वहां के लोगों में कोफ्त तब होती है जब देखते हैं कि पड़ोस के गांव में ये सभी सुविधाएं हैं क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का कोई दमदार समर्थक है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के इस बार के घोषणा पत्र में जो वादे किये गये हैं, उनको भी देखने का अवसर मिल सकता है।इस मामले में कांग्रेस आरोपों से बच सकेगी क्योंकि पिछले डेढ़ दशक से उसे इतनी संख्या में विधायक भी नहीं मिल सके कि सरकार पर विपक्ष में रहते कोई दबाव बना सकती। बिहार में भी कांग्रेस सरकार में शामिल है लेकिन जो भी स्याह–सफेद वहां होता है, उसका श्रेय नीतीश कुमार और लालू यादव के खाते में जा रहा है। इसलिए यूपी में यदि अखिलेश यादव की सरकार बनी और कांग्रेस उसमें बाहर से या अंदर से शामिल रही तो अच्छे–बुरे कार्यों की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी ही जानी जाएगी। फिलहाल, इस सबके लिए 11 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच राज्य के मतदाताओं को अपन कर्तव्य और विवेक निभाना है। मतदाता इतना तो समझते ही हैं कि सरकार कैसे बनती है और प्रतिनिधि का चुनाव किस प्रकार किया जाना चाहिए। कुछ प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो चाहे सत्तारूढ़ दल के हों अथवा विपक्ष के, उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करने का हौसला होता है। अब तो केन्द्र सरकार से उन्हें वह सहूलियत भी प्राप्त है कि विधायकनिधि से ही अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं।

अच्छे कार्य के लिए अगर वे संघर्ष भी करते हैं तो जनता उनका साथ देती है। इसलिए लुभावने वादों का उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों ने जो वादे किये हैं, उनको भी याद रखना होगा और जवाब–तलब के लिए तैयार भी रहना होगा।

बच्चों ने वोट देने के लिए किया प्रेरित

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड्स संस्था की ओर से बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने सर्वप्रथम मतदान उसके बाद अन्य काम का नारा दिया। निबंधन, स्लोगन, पोस्टर व रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने प्रतिभाग किया।मुख्य अतिथि सर्वेंद्र सिंह ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली स्काउट भवन से शुरू होकर गांधी स्टेडियम, छतरी चौराहा, मधुवन, सुनगढ़ी थाना होते हुए स्काउट भवन पर समाप्त हुई। रैली में स्काउट गाइड्स ने सर्वप्रथम मतदाता उसके बाद अन्य काम, मताधिकार का करें प्रयोग आदि नारे देकर लोगों को वोट देने के प्रति प्रेरित किया। पोस्टर, निबंध, रंगोली, स्लोगन प्रतियोगिता में राम इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज, गुरु हरगोविंदर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं ने भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में संगीता मौर्य, स्लोगन प्रतियोगिता में अनुष्का बरुआ, पोस्टर प्रतियोगिता में सोनम रस्तोगी, रंगोली प्रतियोगिता में जान्हवी विजेता घोषित की गई। रैली में मुख्यायुक्त डॉ.राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, जिला स्काउट मास्टर ओम प्रकाश, जिला सचिव सतेंद्र मोहन शर्मा, तोताराम गंगवार, लक्ष्मीदेवी शर्मा, कलीम अतहर खां, गाइड्स कंचन सिंह, रहमत, शालिनी, अभिषेक प्रजापति,योगेश, अर्जुन सिंह, रिया तिवारी, अरु, देवेंद्र मौर्य, रजत कुमार आदि शामिल रहे।

हमारा संकल्प : जागरूक उपभोक्ता-सशक्त राष्ट्र सर्व शिक्षा

इस संकल्प को पूरा करने में आप सब अपना सहयोग देकर भारत के शिक्षा से वंचित बच्चों का भविष्य बनायें

BHARAT JYOTI

भारत ज्योति शिक्षा केन्द्र

(स्थापना वर्ष 2008)

भारत ज्योति शिक्षा केन्द्र

गायत्री नगर, मड़ियाव सीतापुर रोड, लखनऊ

शिक्षा से वंचित निर्धन बच्चों की अपनी पाठशाला
हम सबका संकल्प–हर बच्चे का हो सुनहरा भविष्य

इस संकल्प को पूरा करने में आप सब अपना सहयोग देकर भारत के शिक्षा से वंचित बच्चों का भविष्य बनायें

भारत ज्योति

46, डायमंड डेरी कबीर मार्ग, लखनऊ–226001 फोन–0522–2237899

E-mail : bharat.jyoti@yahoo.co.in Visit : Website : www.bhratjyoti.org

गठबंधन को आकार देकर राजनीति में आ ही गयीं प्रियंका!

–डा0 दिलीप अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश में सपा.कांग्रेस गठबंधन आखिर परवान चढ़ ही गया। कांग्रेस ने हवा में उड़ने की बजाये जमीनी हकीकत समझ कर गठबंधन का जो फैसला लिया है, उससे यूपी में मरणासन स्थिति में पड़ी कांग्रेस में कितनी ऊर्जा पैदा होगी, इस बात का अंदाजा 11 मार्च को परिणाम आने पर लगेगा लेकिन जो दिख रहा है उस पर गौर किया जाये तो राष्ट्रीय दल कांग्रेस जिसका एक समय पूरे देश में राज था, वह अब क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ेगी। वह दल जो कभी कांग्रेस की छत्रछाया में सियासत करते थे, आज कांग्रेस को उन्हीं के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम आदि कई राज्यों में अपना जनाधार खोने के बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस हाशिये पर चली गई है। 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस मात्र 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें से कितनी जीत कर आयेगी यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस जितनी भी सीटों पर चुनाव जीतेगी उसका पूरा श्रेय पार्टी के खाते में नहीं जायेगा। सपा भी उसमें अपनी दावेदारी जतायेगी क्योंकि गठबंधन से पहले ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यह जता दिया था कि वह यूपी में अपने बल पर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखती है। इसीलये सपा.कांग्रेस के बीच गठबंधन की घोषणा के बीच दोनों दलों की ओर से काफी लम्बा क्लाइमेक्स क्रिएट किया गया था। शायद यह गठबंधन काफी पहले आकार ले लेता, लेकिन कांग्रेस द्वारा श्हैसियतश से अधिक दावेदारी ठोकने की वजह से गठबंधन में देरी तो हुई ही इसके साथ.साथ जनता के बीच उसकी किरकिरी भी हुई।गठबंधन के पेंच तो सुलझ गये लेकिन गठबंधन की कोशिशों के दरमयान यह भी साफ हो गया कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस को काफी झुकना पड़ा। गठबंधन अखिलेश और सपा की शर्तों पर ही हुआ। सपा ने पहले ही तय कर लिया था कि कांग्रेस को सौ के करीब सीटें दी जायेंगी और उतने पर ही कांग्रेस को संतोष भी करना पड़ा। असल में कांग्रेस की मजबूरी को सपा नेतृत्व भली भांति समझ गया था। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। उसके मात्र 28 विधायक हैं इसके अलावा 2012 के विधानसभा चुनाव में उसके सिर्फ 26 प्रत्याशी ही नंबर दो पर ठहर पाये थे, जबकि कांग्रेस सीटें सवा सौ से ऊपर चाह रही थी। रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेसी इतने भावुक थे कि वह चाहते थे कि यहां से 2012 में जीती हुई सीटों पर भी सपा चुनाव न लड़े। दरअसल, कांग्रेस की मजबूरी है कि वह अकेले चुनाव जीत ही नहीं सकती है और अन्य कोई दल उसे तवज्जो दे नहीं रहा है। ऐसे में एक निजी समाचार चौनल के कार्यक्रम के दौरान अखिलेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का शिगूफा छोड़ा तो पार्टी की बांछें खिल गईं। कांग्रेसी सपा के सहारे सत्ता का स्वाद चखने का सपना देखने लगे। बड़ी.बड़ी बातें करने वाले कांग्रेसियों को जरा भी इस बात की चिंता नहीं रही कि इससे उसके भविष्य की देशव्यापी राजनीति पर कितना कुप्रभाव पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त पड़ जायेंगे। असल में कांग्रेस के प्रति सपा नेतृत्व ने जो रवैया अख्तियार कर रखा था, उसे सहना कांग्रेस की मजबूरी बन गई है। इसी के चलते वह सपा से धोखा खाने तक से परहेज नहीं कर रही थी। बहरहाल, सीटों के बंटवारे और अहं के टकराव को लेकर अधर में दिख रहे कांग्रेस.सपा के गठबंधन को उस समय नई जान मिल गई जब प्रियंका गांधी ने गठबंधन बनवाने के कार्य की कमान संभाली, कांग्रेस के दूत प्रशांत किशोर को बातचीत के लिये आगे किया गया। तब जाकर बात बन पाई, मगर सपा की शर्तों पर। अब गठबंधन हो गया है। परंतु इसमें कई किन्तु.परंतु भी लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल और अखिलेश कितनी जगह संयुक्त रैलियां करेंगे और जब राहुल. अखिलेश चुनाव प्रचार में एक साथ जायेंगे तो तो दोनों में से कौन बड़ा नजर आयेगा। राहुल को शायद ही बर्दाश्त हो कि अखिलेश उनके सामने श्लम्बी लाइनश खींचें। लब्बोलुआब यह है कि इस गठबंधन से फायदा तो दोनों ही दलों को होगा, मगर कांग्रेस को यूपी में सपा की बी टीम बनकर ही रहना पड़ेगा। संभावना इस बात की भी है कि 2019 तक तो यह गठबंधन किसी तरह से खिंचता रहेगा लेकिन लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश और राहुल की महत्वाकांक्षा में टकराव पैदा हो सकता है। इतिहास में भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस और सपा के संबंध हमेशा कलह से भरे रहे हैं। आज भले ही कांग्रेस और सपा करीब हों लेकिन सोनिया गांधी यह नहीं भूल सकती हैं कि मुलायम की वजह से वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकी थीं तो मुलायम को भी हमेशा इस बात का मलाल रहा कि लालू के कहने पर सोनिया गांधी ने उनके प्रधानमंत्री बनने की राह में अवरोध पैदा किया था। यूपी के पुराने कांग्रेसी नेता जानते.मानते हैं कि आज जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा है, उसका कारण सपा ही है। फिर भी कांग्रेस ने ये गठबंधन करके बड़ा रिस्क लिया है। उधर, चर्चा यह भी है कि यूपी विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर का रुख भी तय कर सकते हैं। राहुल की लगातार नाकामयाबी और राजनीति में उनकी अरूचि के चलते अक्सर प्रियंका को आगे किये जाने की बात चलती रहती है। जिस तरह अहमद पटेल ने गठबंधन के मामले में प्रियंका का नाम लेकर ट्वीट किया उससे भी साफ जाहिर है कि प्रियंका विधिवत रूप से सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं। वैसे, एक बात पर और ध्यान दिया जाना जरूरी है। सपा.कांग्रेस के इस गठबंधन में साल 2004 के लोकसभा चुनावों की झलक भी देखने को मिल रही है। उस समय तत्कालीन एनडीए सरकार को हटाने के लिये सोनिया गांधी ने तमाम क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की थी और अब उसी फार्मूले का राहुल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस खेल के पीछे असली भूमिका प्रियंका गांधी की है। प्रियंका की बदौलत ही ये गठबंधन पूरा हो सका। प्रियंका की कोशिश है कि सपा. कांग्रेस के गठजोड़ को महागठबंधन के तौर पर पेश किया जाए और देशभर की गैर भाजपा विरोधी पार्टियों को इस बहाने एक साथ ला कर 2019 की तैयारी की जा सके। इस गठबंधन में सोनिया. मुलायम वाली तल्खी नहीं, प्रियंका और डिंपल की जुगलबंदी है। अगर इस गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल भी बन जाता तो यह श्सोने पर सुहागाश हो सकता था। कुछ राजनैतिक पंडित तो यह भी कहते हैं कि 2019 लोकसभा की लड़ाई शुरू हो गई है। बीतते समय के साथ आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक गठबंधन नजर आएंगे। वैसे, यूपी चुनाव में गठबंधन का इतिहास काफी पुराना है। कभी कांग्रेस.सपा जैसा गठबंधन सपा.बसपा के बीच भी हुआ था।

कांग्रेस दर्शा कुछ और रही थी प्रयास सिर्फ गठबंधन का था

अंततः कांग्रेस और सपा दोनों की मुराद पूरी हुई। गठबंधन मुकम्मल हुआ। इसी के साथ साबित हुआ कि दोनों में से कोई अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अब तक जो आंख मिचौली चल रही थी वह एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए थी। सौदेबाजी में बढ़त के लिए दावे किए जा रहे थे। इनको देखकर हकीकत का अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। गठबन्धन होगा, तो देखा जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही थी, उसे 105 पर सिमटने में देर नहीं लगी। कांग्रेस के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष बेचैनी से दिल्ली लखनऊ एक किए हुए थे। इन्हें देखकर लग रहा था कि ये गठबन्धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो पार्टी दूसरे चरण का नामांकन शुरू होने के बाद पहले चरण के बाद पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी हो, वह कितनी तैयार थी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले राज बब्बर और शीला दीक्षित को चुनावी

समर में इस तरह भेजा गया था, जैसे वह कांग्रेस को विजय की सौगात दिलाकर ही मानेंगे, लेकिन इधर नामांकन शुरू हुए उधर शीला दीक्षित तस्वीर से हटने लगीं।

राज बब्बर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश से मिलने की प्रतीक्षा में रोके गए। हाईकमान से निर्देश मिल रहे थे। प्रत्याशी चयन, प्रचार सब कुछ पीछे रह गए। सपा का रूख पता करना प्राथमिकता हो गयी। चुनाव में कांग्रेस को गठबन्धन से कितना फायदा होगा, यह तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन इसका संगठन व मनोबल किस मुकाम पर है, इसका खुलासा अवश्य हो गया। जिस प्रकार सपा से गठबन्धन का जोर लगाया गया वह पूरी कहानी बयान करता है। अब तो यह लगता है कि कांग्रेस ने चुनावी मैनेजर की सेवायें केवल गठबन्धन के लिए ली थीं। इसके लिए उसने अपना पूरा संगठन अनौपचारिक रूप से उन्हीं के हवाले कर दिया था। पार्टी को धीरे.धीरे गठबन्धन की ओर ही बढ़ाया जा रहा था। कार्यकर्ताओं को धोखे में रखने के लिए ही कुछ परिवर्तन दिखाया जा रहा था। अध्यक्ष पद से निर्मल खत्री को हटाया गया। राज बब्बर को उनकी जगह लाया गया। जबकि कुछ समय पहले वह समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। वह अपने को जन्मजात समाजवादी मानते थे। कार्यकार्ताओं को दिखाया गया कि राज बब्बर भीड़ जुटायेंगे। पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। फिर कवायद यहीं तक सीमित नहीं रही। उसने आगे बढ़कर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि शीला दीक्षित के नेतत्व में कांग्रेस सरकार बनायेंगी। श्27 साल यूपी बेहालश अभियान तो पार्टीजनों को भ्रमित करने के लिए था। यह बताया गया कि पीके कांग्रेस की बेहाली दूर कर देंगे।

कार्यकर्ताओं ने भीड़ जुटाने के लिए मेहनत भी की। फिर कहा गया कि शीला दीक्षित ब्राह्मणों का वोट हासिल कर लेंगी। पिछड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन भी हुए, लेकिन पीके की यह दिखावटी तैयारी थी। वह कांग्रेस हाईकमान की पूरी जानकारी में सपा से गठबन्धन की गोटी चल रहे थे। इसलिए कार्यकर्ता खटिया लाकर सभा की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन राहुल के श्27 साल यूपी बेहालश से सपा नदारद थी। जब मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई तो औपचारिकता निभाने को उन्होंने सपा का नाम लिया, लेकिन राहुल बता यही रहे थे कि नरेन्द मोदी के ढाई साल में यूपी 27 साल से बेहाल हो गयी। कुछ समय बाद राहुल विदेश में छुट्टी मानने चले गए। उधर सपा अपनी पारिवारिक कलह में उलझी थी। कांग्रेसी प्रबन्धक समझ ही नहीं पा रहे थे कि किससे बात करें। लड़ाई सपा में थी लेकिन कांग्रेस में गतिविधियां सुस्त पड़ गयी थीं।

इधर सपा की लड़ाई थमी, उधर मैनेजर व उनके एक सहयोगी सक्रिय हो गये। बताया गया कि ये प्रियंका वाड्रा के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने सीधे अखिलेश से वार्ता की तो बात बन गयी। अब सपा की स्थिति पर विचार कीजिए। पारिवारिक कलह से अखिलेश यादव विजेता बनकर उभरे थे। पूरी पार्टी उनकी हो चुकी थी। इसके पहले प्रचार में भी उनका मंसूबा देखते बनता था। कहा जा रहा था कि सारे वादे पूरे हो गये। लग रहा था कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन में उनकी पार्टी की दिलचस्पी कम नहीं थी। अकेले चुनाव लड़ने का साहस सपा भी जुटा नहीं पा रही थी।

कांग्रेस जैसी पार्टी से गठबन्धन से बड़ी उम्मीद करना अजीब लग सकता है, लेकिन वोट बैंक के मकसद से यह सौदा किया गया। इससे जाहिर है कि सपा को अपने विकास संबंधी मुददों पर विश्वास नहीं रहा। सपा कांग्रेस के गठबन्धन से बसपा को अवश्य परेशानी हुई है। पहले विधानसभा चुनावों में पराजय फिर लोकसभा में सूपड़ा साफ होने के बाद मायावती का सवर्णों के प्रति विश्वास डगमगाया था। लोकसभा चुनाव में तो उनके दलित वोट में भी सेंध लगी थी। उन्हें लग रहा था कि सपा.कांग्रेस का गठबन्धन नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें सपा में विभाजन की पूरी उम्मीद थी।

अनुष्का शर्मा बनेंगी स्वच्छ भारत अभियान का चेहरा

अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अब जल्द ही प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ कर लोगों को साफ–सफाई का पाठ पढ़ाएंगी। वह स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरुकता फैलाएंगी। शहरी विकास मंत्रालय ने अनुष्का को स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपने ब्रैंड फेस के तौर पर फाइनल किया है। इस मुहीम से अनुष्का को जोड़ने का मकसद है कि सफाई अभियान का सन्देश ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे। जिससे भारत के गांव की महिलायें स्वच्छता को लेकर जागरूक हों।

ऐक्ट्रेस और प्रड्यूसर अनुष्का को मंत्रालय ने खास तौर पर महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए चुना है। ताकि वह साफ सफाई और महिलाओं की सेहद से जुड़े तमाम पहलुओं को सामने ला सकें साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को महिलाओं तक पहुंचा सकें।

कई पब्लिक प्लैटफॉर्म ऐसे इलाकों में हैं जहां महिलाओं के लिए टॉयलेट की जरुरत होती है लेकिन वहां टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है। यह महिलाओं की सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी फिल्मों के जरिए अनुष्का हमेशा महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हैं, ऐसे में सरकार को लगता है अनुष्का का चेहरा और आवाज महिलाओं की आवाज को ताकत देगी।

खबरों की माने तो अनुष्का ने इस मुहीम से संबधित दो मुख्य विडियो भी शूट कर लिए हैं। अनुष्का स्वच्छ भारत और महिलाओं की सेहद से जुड़े इस मुहीम में अपने सुझाव भी दे रहीं हैं। इस अभियान से विद्या बालन और अमिताभ बच्चन भी जुड़े हैं जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को घर में टॉयलेट होने के फायदे बताते हैं।

शाहरुख संग काम कर काफी कुछ सीखने को मिला : भगवान तिवारी

टेलीविजन धारावाहिक 'गुलाम' में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अभिनेता भगवान तिवारी सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ 'रईस' में काम कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करने का अनुभव सीखने वाला था. फिल्म 'रईस' में भगवान गुजराती पुलिसकर्मी की भूमिका में हैं।भगवान ने कहा, "बॉलीवुड के बादशाह के साथ काम का अनुभव पूरी तरह अलग रहा, क्योंकि यहां बहुत–सी चीजें सीखने को मिलीं. मैं बहुत खुश हुआ, जब उन्होंने मेरी प्रशंसा की।

टेलीविजन चौनल लाइफ ओके के स्टार ने कहा कि जब उन्होंने शाहरुख के साथ काम किया तब उन्हें पता चला कि 'चेन्नई एक्प्रेस' के स्टार को सुपरस्टार के तौर पर क्यों जाना जाता है।

बद्रीनाथ की दुल्हनियां के पोस्टर पर छाए वरुण और आलिया, ये है रिलीज डेट

दो दिन पहले आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनियां का पहला टीजर जारी हुआ था। अब इसका पोस्टर जारी हुआ है। इस फिल्म का ट्रेलर दो फरवरी को आ रहा है।

पोस्टर में फिल्म की लीडिंग स्टारकास्ट ही छाए हुए हैं। आलिया और वरुण को यहां देसी अंदाज में देखा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि ट्रेलर का मुहूर्त गुरूवार को दोपहर बारह बजे का है। फिल्म को 10 मार्च को रिलीज किया जाएगा। यह होली के तीन दिन पहले रिलीज हो रही है।

वैसे इसका फर्स्ट लुक तो दो महीने पहले ही जारी कर दिया गया था। फिल्म के अभिनेता वरुण धवन अपने ट्विटर अकाउंट से फिल्म से जुड़ी तस्वीरें भी साझा करते रहते हैं।

इसकी शूटिंग सिंगापुर में भी हुई है। गौरतलब है कि श्बद्रीनाथ की दुल्हनियांश एक लव स्टोरी है, जिसमें झांसी के एक लड़के बद्रीनाथ और लड़की वैदेही की कहानी है।

बद्रीनाथ के किरदार में एक्टर वरुण धवन नजर आएंगे और वैदेही के किरदार में एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं। फिल्म ष्हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियांष के बाद ये दोनों कलाकार एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं। यह फिल्म कोई सीक्वल नहीं है।

पहले टीजर में सिर्फ वरुण धावन ही दिख रहे हैं। इसे देखना मजेदार है क्योंकि वरुण ने कमाल के एक्सप्रेशन दिए हैं।

राष्ट्र हित में ऊर्जा बचाएं

उपभोक्ता जागरूकता एवं सहायता केन्द्र

BHARAT JYOTI

भारत ज्योति उपभोक्ता सूचना केन्द्र द्वारा संचालित

उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं सलाह व सहायता के लिये भारत ज्योति के विभिन्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

1. चिकित्सा सेवायें 2. रियल इस्टेट 3. शिक्षा 4. पेट्रोलियम व गैस 5. बैंक एवं बीमा 6. ड्रग एवं केमिस्ट 7. कृषि 8. दूरसंचार (मोबाइल, फोन, पोस्टल, टीवी चैनल आदि) अन्य सेवायें जैसे रेल ट्रांसपोर्ट बाजार की खरीद फरोख्त संबंधी, इलेक्ट्रानिक व टीवी एसी इत्यादि के साथ–साथ केसी व्यवसायिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें आदि।

सावधान–• खरीद की रसीद अवश्य लें सेवा लेने से पहले शर्तें अवश्य पढ़ें। • तराजू और बांट परखें। • पेट्रोल पम्प में माप व शुद्धता जांचने का प्राविधान है। उसे भी कभी–कभी जांचे। दवा हो या कैसी भी खाने की पैक वस्तु हो तारीख व मूल्य देखें।

अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं–फोन–0522 2237899 या डाक द्वारा भेज सकते हैं– भारत ज्योति, 46, डायमण्ड डेरी, कबीर मार्ग, लखनऊ–226001 अथवा

Email bharat.jyoti@yahoo.co.in visit.website:bharatjyoti.org

"जागरूक उपभोक्ता राष्ट्र की निधि है–विजय आचार्य"

Regd. Office Bharat Jyoti, 46 Diamand Dairy Kabir Marg, Lucknow-226 001
Tel.: 0522-2237899, 9415028127, Email ; bharat.jyoti@yahoo.co.in, Website :www.bharatjyoti.org

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक भारत ज्योति द्वारा हिन्दुस्तान समाचार फीचर सेवा लि0 94, महात्मा गांधी मार्ग हजरतगंज लखनऊ से मुद्रित एवं 46, डायमंड डेरी, कबीर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित फोन–0522–2237899 सम्पादक : विजय आचार्य समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ ही होगा।